



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61776

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8320 वर्ष 2026

रोहित सोनकर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: नितेश कुमार सिंह, रबिंद्र तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम आनंद, राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 5/2026, धारा 191(2), 126(2), 131, 115(2), 352, 351(2), 105 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- लालपुर पांडेपुर, जिला- वाराणसी में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 4.1.2026 को घटी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट 5.1.2026 को दर्ज की गई थी। प्रथम

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूचना रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। शिकायतकर्ता उसे इलाज के लिए ले जा रहा था। रास्ते में, कुछ लोगों ने ठेले (ठेला/सागड़ी) लगाकर सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था। शिकायतकर्ता ने अवरोध हटाने का अनुरोध किया क्योंकि उसकी पत्नी अस्वस्थ थी। हालांकि, आवेदकों ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शिकायतकर्ता को गंदी भाषा में गाली देना शुरू कर दिया और उसे धक्का दिया। इसके बाद, उन्होंने शिकायतकर्ता पर लातों और घूंसे बरसाए। शोर सुनकर उसकी पत्नी घर से बाहर आई और उसने बीच-बीच करने की कोशिश की। उस समय, आवेदक ने चार अन्य आरोपियों और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की पत्नी को लातों और घूंसे मारकर बुरी तरह पीटा, खासकर उसके पेट पर वार किए। इसके परिणामस्वरूप, उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं और खून बहने लगा। शिकायतकर्ता की पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यह दावा किया जाता है कि शिकायतकर्ता की पत्नी की उसी दिन मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर ने दो चोटें दर्ज कीं। चोट संख्या 1:- सर्जिकल लैपरोटॉमी 21 सेमी लंबा, ऊर्ध्वाधर रूप से लगा हुआ, काले टांकों वाला घाव, पेट के सामने मध्य रेखा पर, ऊपरी भाग में नाभि के स्तर पर और निचले भाग में प्यूबिक सिम्फिसिस पर स्थित है। जांच करने पर, कोलन के मलाशय पर कई काले टांके मौजूद थे (जो मलाशय की मरम्मत का संकेत देते हैं)। गर्भाशय के निचले भाग में और लगभग 5 सेमी गर्भाशय ग्रीवा क्षेत्र में कई काले टांके मौजूद थे (जो हिस्टेरेक्टॉमी का संकेत देते हैं)। पेरिटोनियम परतों के निचले भाग के बाईं ओर चोट का निशान मौजूद था। चोट संख्या 2:- 5 सेमी x 3.5 सेमी का सिला हुआ घाव, पेट के सामने के दाहिने भाग पर, मध्य रेखा से 9 सेमी बाहर और एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से 4 सेमी ऊपर स्थित है (जो इलियोस्टॉमी का संकेत देते हैं)। आगे यह तर्क दिया गया है कि चिकित्सा संबंधी बयान अभियोजन पक्ष के मामले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की पुष्टि नहीं करता है। डॉक्टर की राय के अनुसार, मृत्यु का कारण आंतरिक अंगों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही बताया जाएगा। आंतरिक अंगों की रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी राजा सोनकर और प्रमोद सोनकर को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.3.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6912/2026 (राजा सोनकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। आवेदक समानता की मांग करता है। आवेदक 19.1.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन रिकॉर्ड से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि चिकित्सा विवरण अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि नहीं करता है। डॉक्टर की राय के अनुसार, मृत्यु का कारण विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही बताया जाएगा। विसरा रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका नहीं जताई गई है कि यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे या गवाह को डराएंगे। मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. उपर्युक्त मामले में आरोपी रोहित सोनकर को जमानत पर रिहा किया जाए। ब्याज पर रिहा करने के लिए, बशर्ते वह एक निजी मुचलका और दो जमानती पेश करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो। निम्नलिखित शर्तों पर:

- i. आरोपी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- iii. आरोपी अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

25 मार्च, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”